

माँग की लोच का महत्व

(IMPORTANCE OF ELASTICITY OF DEMAND)

माँग की लोच की अवधारणा का सैद्धान्तिक महत्व के साथ-साथ विभिन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान में भी महत्व है। इसके महत्व के सम्बन्ध में कीन्स ने कहा है—“मार्शल की सबसे बड़ी देन माँग की लोच का सिद्धान्त है तथा इसके अध्ययन के बिना कीमत तथा वितरण के सिद्धान्तों की व्याख्या सम्भव नहीं है।”

माँग की लोच का व्यावहारिक महत्व निम्नलिखित है :

1. मूल्य-निर्धारण में सहायक (Helpful in the determination of price)—
किसी वस्तु के मूल्य-निर्धारण में माँग की लोच का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि किसी वस्तु की माँग लोचदार है तो उत्पादक उस वस्तु की कीमत यथासम्भव कम रखने का प्रयास करेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की कीमत अधिक रखने से माँग घट जायेगी और जिससे उत्पादक को घाटा अथवा कम मुनाफा प्राप्त होगा। इसके विपरीत, जिन वस्तुओं की माँग की लोच बेलोचदार होती है, उनकी कीमत अधिक रखी जा सकती है, क्योंकि अधिक कीमत पर भी उनकी माँग नहीं घटेगी। इस प्रकार माँग की लोच को ध्यान में रखकर यदि कोई उत्पादक अपनी वस्तुओं का मूल्य

निर्धारण करता है, तो उसे अधिक लाभ होगा। मुख्य रूप से माँग की लोच के अध्ययन से एक एकाधिकारी अधिक लाभान्वित हो सकता है, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभार्जन करना होता है।

2. **वित्त मंत्री के लिये महत्व (Importance for Finance Minister)**—किसी भी देश के वित्त मंत्री को वस्तुओं पर कर (Tax) लगाने के पूर्व उनकी माँग की लोच का अध्ययन करना आवश्यक होता है। जिन वस्तुओं की माँग की लोच लोचदार होती है, उन पर कम कर तथा जिनकी माँग बेलोचदार होती है, उन पर अधिक कर लगाया जाता है। ऐसा इसलिये कि बेलोचदार वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाने पर भी माँग अप्रभावित रहती है, जबकि लोचदार वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने से उनकी माँग शीघ्र ही प्रभावित हो जाती है अर्थात् घट जाती है।

3. **रेल किराया के निर्धारण में (In determination of railway fare)**—रेलवे भाड़ा के निर्धारण में भी माँग की लोच का महत्वपूर्ण स्थान है। जिन यात्रियों की माँग की लोच लोचदार होती है, उनके लिये रेलवे भाड़ा कम निर्धारित किया जाता है। ऐसे यात्री खासकर गरीब तबके के लोग होते हैं। यदि रेलवे भाड़ा में वृद्धि हो जाती है, तो ऐसे यात्री वैकल्पिक वाहन (बस) का प्रयोग करने लगेगे, जिससे रेलवे विभाग की आय घट जायेगी। दूसरी ओर, ऐसे यात्री जिनकी माँग की लोच बेलोचदार होती है (अमीर यात्रियों की) उनके लिये रेलवे किराया अधिक निर्धारित किया जाता है। ये रेलवे भाड़ा में वृद्धि के बावजूद भी रेलवे से ही यात्रा करना पसन्द करते हैं और रेलवे विभाग की आय में कटौती नहीं होकर वृद्धि होती है।

4. **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में (In international trade)**—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भी माँग की लोच का महत्व कम नहीं है। जिन वस्तुओं की माँग की लोच बेलोचदार होती है और उनका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, तो उनकी कीमत अधिक निर्धारित की जाती है, क्योंकि अधिक कीमत पर भी उनकी माँग विदेशों में कम नहीं होती है। इसके विपरीत, जिन वस्तुओं की माँग की लोच लोचदार होती है, उनकी कीमत कम निर्धारित की जाती है, जिससे उनकी माँग विदेशों में बनी रहे।

5. **वितरण सिद्धान्त में प्रयोग (Use in the theory of distribution)**—उत्पादन के साधनों का पारिश्रमिक निर्धारित करना भी एक जटिल काम है। अतः इस सन्दर्भ में भी माँग की लोच को ध्यान में रखना उत्पादकों के लिये निहायत जरूरी होता है। जिन साधनों की माँग की लोच लोचदार होती है, उनका पारिश्रमिक अधिक निर्धारित किया जाता है, अन्यथा उनकी पूर्ति घट जायेगी, जिससे उत्पादन की क्रिया प्रभावित हो जायेगी। इसके विपरीत, जिन साधनों की माँग की लोच बेलोचदार होती है, उनका पारिश्रमिक कम निर्धारित किया जाता है, क्योंकि कम पारिश्रमिक पर भी उनकी पूर्ति घटती नहीं है।

6. **संयुक्त पूर्ति की वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में (In the determination of price of goods having joint supply)**—यहाँ संयुक्त पूर्ति की वस्तुओं का उदाहरण है सरसों का तेल एवं खली। इन वस्तुओं की अलग-अलग लागत ज्ञात करना एक जटिल कार्य होता है। ऐसी स्थिति में माँग की लोच का सहारा लिया जाता है। जिन वस्तुओं की माँग की लोच बेलोचदार होती है उनकी लागत अधिक आँकी जाती है जिससे उनकी कीमत बढ़ जाती है और बढ़ी हुई कीमत पर भी उनकी माँग घटती नहीं। इसके विपरीत, जिन वस्तुओं की माँग की लोच लोचदार होती है, उनकी लागत कम आँकी जाती है जिससे उनकी कीमत भी कम होती है। कम कीमत निर्धारित होने से उनकी माँग बढ़ती है, घटती नहीं।

7. **आर्थिक नीति के निर्धारण में (In determination of economic policy)**—सरकार को अपनी आर्थिक नीति के निर्धारण में भी माँग की लोच की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण

के लिये, मुद्रा-स्फीति (Inflation) तथा मुद्रा-विस्फीति (Deflation) की समस्या को दूर करने में भी सरकार को माँग की लोच को ध्यान में रखना होता है। माँग की लोच से सरकार को इस सन्दर्भ में सहायता मिलती है कि किन-किन उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में लिया जाय। अतः जिन वस्तुओं की माँग की लोच बेलोचदार हो और एकाधिकारी अधिक कीमत वसूल कर जनता का शोषण कर रहे हों, उनसे सम्बन्धित उद्योगों को जनहित में सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए।